गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 254
दि. 14.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आसमान में भारत की बढ़ती ताकत: फ्रांस के साथ ऐतिहासिक राफेल सौदे की दहलीज पर देश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। बदलते वैश्विक हालात, सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच भारत और फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील लगभग फाइनल मानी जा रही है। इस प्रस्ताव के तहत भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, जिनकी कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये आंकी जा रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस हफ्ते उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, जिसके बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा।

यह सौदा केवल विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति और आत्मनिर्भर रक्षा नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, 114 में से 12 से 18 राफेल विमान पूरी तरह तैयार अवस्था में सीधे भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे, ताकि स्क्वाड्रनों की घटती संख्या को तुरंत संतुलित किया जा सके। शेष विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री और भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि तकनीकी कौशल, रोजगार और भारत की औद्योगिक क्षमता को भी बड़ा लाभ होगा।

भारत इस डील के जरिए यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में राफेल विमानों में भारतीय हथियार प्रणालियों और सेंसरों को आसानी से जोड़ा जा सके। हालांकि विमानों का सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेगा, लेकिन ऑपरेशनल स्वतंत्रता के लिहाज से भारत को पर्याप्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में राफेल के M-88 इंजन के रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेष सुविधा विकसित करेगी। इसके साथ ही टाटा जैसी भारतीय कंपनियां भी निर्माण और मेंटेनेंस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगी, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन श्रृंखला और मजबूत होगी। राफेल को फिर से प्राथमिकता दिए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका युद्धक्षेत्र में साबित प्रदर्शन है। हाल के सैन्य अभियानों, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राफेल ने अपनी अत्याधुनिक तकनीक, लंबी मारक क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए दुश्मन की मिसाइलों और हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय किया। इस ऑपरेशन ने भारतीय वायुसेना के भरोसे को और पुख्ता किया कि राफेल आधुनिक युद्ध की जटिल परिस्थितियों में भी पूरी तरह सक्षम है। यही वजह है कि वायुसेना नेतृत्व ने नए लड़ाकू विमानों के चयन में राफेल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

इस सौदे को और भी अहम बनाता है यह तथ्य कि अमेरिका और रूस जैसे देश भारत को अपने अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57, ऑफर कर चुके हैं। इसके बावजूद भारत ने राफेल को चुना। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे रणनीतिक निरंतरता और व्यावहारिकता सबसे बड़ा कारण है। राफेल पहले से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, इसके पायलट प्रशिक्षित हैं, ग्राउंड स्टाफ और लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार हैं और इसकी ऑपरेशनल क्षमताएं भारतीय जरूरतों के अनुरूप साबित हो चुकी हैं। नए प्लेटफॉर्म को शामिल करने की तुलना में राफेल की संख्या बढ़ाना समय, लागत और रणनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावी विकल्प माना गया।

वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में इस सौदे का महत्व और बढ़ जाता है। एक ओर एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है, दूसरी ओर सीमाओं पर तनाव और वैश्विक स्तर पर जारी संघर्ष भारत के लिए सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना को अधिक संख्या में आधुनिक, भरोसेमंद और मल्टी-रोल लड़ाकू विमानों की जरूरत है। आने वाले वर्षों में वायुसेना की रीढ़ मुख्य रूप से Su-30 MKI, राफेल और स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर आधारित होगी, जिससे भारत की हवाई मारक क्षमता और रणनीतिक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

यदि यह डील मंजूर हो जाती है तो भारत के पास राफेल विमानों की कुल संख्या 176 हो जाएगी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल पहले से सेवा में हैं और भारतीय नौसेना ने भी 26 राफेल मरीन विमानों का ऑर्डर दिया है। इस तरह राफेल भारत की वायु और समुद्री सुरक्षा का एक अहम स्तंभ बन जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में राफेल विमानों की मौजूदगी भारत को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। कुल मिलाकर, भारत और फ्रांस के बीच प्रस्तावित यह डिफेंस डील महज एक हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। यह सौदा आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की दिशा और क्षमता तय करेगा और यह संदेश देगा कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है।

वैश्विक मंच पर भारत की नई भूमिका: ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के साथ 'नमस्ते' से दुनिया को संवाद का संदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बदलती वैश्विक राजनीति, आर्थिक अनिश्चितताओं और बहुपक्षीय व्यवस्था में उभरती चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंगलवार को भारत ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता ग्रहण कर ली। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की थीम, लोगो और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए संकेत दिया कि भारत इस बहुपक्षीय मंच को अधिक जन-केंद्रित, समावेशी और व्यावहारिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अवसर केवल एक औपचारिक हस्तांतरण नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक सोच और कूटनीतिक दृष्टि को रेखांकित करने वाला क्षण भी रहा।

विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहां भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक असमानताएं और संस्थागत सुधार की मांगें एक साथ सामने आ रही हैं। ऐसे में ब्रिक्स जैसे मंच की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने जोर दिया कि ब्रिक्स को केवल एक आर्थिक समूह के रूप में नहीं, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की साझा आवाज के रूप में काम करना होगा। भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य इसी सामूहिक आवाज को मजबूती देना और सुधारित बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना है, ताकि वैश्विक शासन संरचनाएं अधिक न्यायसंगत और संतुलित बन सकें।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का यह चौथा अवसर है। इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी भारत इस समूह की अगुवाई कर चुका है। विशेष रूप से 2021 का दौर कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से भरा था, जब भारत ने डिजिटल माध्यमों के जरिए सहयोग और संवाद को आगे बढ़ाया था। अब 2026 में भारत ऐसे समय में अध्यक्षता संभाल रहा है, जब ब्रिक्स समूह अपने अस्तित्व के दो दशक पूरे करने जा रहा है। जयशंकर ने इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने खुद को उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सहयोग के एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित किया है। ब्रिक्स की यात्रा पांच देशों से शुरू हुई थी, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। समय के साथ इसका दायरा बढ़ा और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देश पूर्ण सदस्य बने। आज यह समूह 10 देशों का ऐसा मंच बन चुका है, जो वैश्विक जनसंख्या, ऊर्जा संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है। भारत की अध्यक्षता ऐसे समय में आई है, जब इस विस्तारित ब्रिक्स को आंतरिक समन्वय, साझा प्राथमिकताओं और वैश्विक प्रभाव के नए संतुलन की आवश्यकता है।

भारत ने अपनी अध्यक्षता को सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक रूप से भी विशिष्ट बनाने का प्रयास किया है। ब्रिक्स 2026 के लिए चुना गया लोगो भारत के राष्ट्रीय फूल 'कमल' पर आधारित है, जिसके केंद्र में भारतीय अभिवादन 'नमस्ते' को दर्शाया गया है। यह लोगो केवल एक डिजाइन नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत सोच और संवाद की परंपरा का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा नागरिक सहभागिता मंच पर आयोजित खुले प्रतियोगिता के जरिए इस लोगो का चयन किया गया, जिसमें अंततः सुदीप सुभाष गांधी के डिजाइन को चुना गया। जयशंकर ने कहा कि 'नमस्ते' सम्मान, स्वागत और संवाद का प्रतीक है, और यही भावना भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान वैश्विक मंच पर लेकर जाना चाहता है।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से अपेक्षा की जा रही है कि वह विकास, वित्त, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर ठोस पहल करेगा। भारत पहले ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, समावेशी विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है। ऐसे में ब्रिक्स मंच के जरिए इन अनुभवों को साझा करने और सामूहिक समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। भारत का यह भी प्रयास रहेगा कि ब्रिक्स केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि ठोस नीतिगत और व्यावहारिक परिणामों की ओर बढ़े।

राजधानी से सपनों की रफ्तार: आखिरी मोड़ पर दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, बिना पिलर के पुल से बदलेगी एनसीआर की तस्वीर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। डीएनडी फ्लाईवे से जैतपुर तक का खंड, जिसे राजधानी के लिए एक गेमचेंजर माना जा रहा है, लगभग तैयार हो चुका है और निर्माण कार्य अंतिम सांसें गिन रहा है। इस हिस्से के पूरा होते ही न केवल दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर की यातायात व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। यह वही परियोजना है, जिससे जुड़ी उम्मीदें वर्षों से आम नागरिकों, उद्योग जगत और परिवहन क्षेत्र के लिए एक नए युग का संकेत मानी जा रही हैं। इस खंड की सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली विशेषता आगरा कैनाल पर बन रहा अत्याधुनिक स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे बिना किसी पिलर के डिजाइन किया गया है। शुरू में यहां एक सामान्य कंक्रीट पुल बनाने की योजना थी, लेकिन तकनीकी अध्ययन और पर्यावरणीय चिंताओं के बाद डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया। आगरा कैनाल दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए जल प्रवाह की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का मानना था कि अगर नहर के बीच पिलर बनाए गए तो भविष्य में जल प्रवाह बाधित हो सकता है और बाढ़ जैसी स्थितियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी वजह से पुल को बिना पिलर के स्टील आर्च तकनीक से तैयार किया जा रहा है, जो भारत में गिनी-चुनी जगहों पर ही देखने को मिलती है। डिजाइन में इस बदलाव का असर परियोजना की लागत पर भी पड़ा है। जहां पहले इस खंड की लागत कम आंकी गई थी, वहीं अब करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च जुड़ गया है। इसके बाद इस हिस्से की कुल लागत 1836 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और परियोजना से जुड़े इंजीनियरों का मानना है कि यह खर्च केवल एक पुल पर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की सुरक्षित, टिकाऊ और निर्बाध यातायात व्यवस्था पर किया गया निवेश है।

'केरल' से 'केरलम' तक: नाम बदलने के प्रस्ताव पर भाजपा का समर्थन, भाषा संस्कृति और राजनीति के नए मायने

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। केरल का नाम बदलकर 'केरलम' किए जाने के प्रस्ताव को लेकर राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की इस पहल को अब भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई का भी समर्थन मिल गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी राज्य का नाम उसके पारंपरिक और भाषायी स्वरूप 'केरलम' में किए जाने के पक्ष में है। इस समर्थन को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आम तौर पर भाजपा और वाम दलों के बीच वैचारिक दूरी बनी रहती है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों की राय एक जैसी दिखाई दे रही है।

राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने से न केवल स्थानीय भाषा और संस्कृति को सम्मान मिलेगा, बल्कि उन ताकतों पर भी अंकुश लगेगा, जो धर्म के आधार पर राज्य को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की बात करती हैं। उनके अनुसार, नाम को लेकर होने वाली यह पहल राज्य की एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। भाजपा का यह तर्क भी सामने आया है कि जब किसी क्षेत्र की पहचान उसकी भाषा और परंपरा से जुड़ी होती है, तो उसका नाम भी उसी अनुरूप होना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि केरल विधानसभा पहले ही आधिकारिक अभिलेखों में राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उनका कहना है कि भाजपा की विचारधारा हमेशा से भाषायी विविधता, सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय पहचान के संरक्षण पर आधारित रही है। इसी सोच के तहत पार्टी राज्य को उसके पारंपरिक नाम 'केरलम' से संबोधित करती रही है, जो हजारों वर्षों की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मुताबिक, नाम में यह बदलाव किसी राजनीतिक एजेंडे से अधिक सांस्कृतिक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है।

'केरलम' शब्द का महत्व केवल एक नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मलयालम भाषा में 'केरलम' का अर्थ नारियल के पेड़ों की भूमि माना जाता है, जो राज्य की पहचान का एक प्रमुख प्रतीक है। समुद्र तटों से लेकर गांवों और कस्बों तक फैले नारियल के पेड़ केरल की अर्थव्यवस्था, खान-पान और जीवनशैली का अहम हिस्सा रहे हैं। इतिहासकारों और भाषाविदों का मानना है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को 'केरलम' के नाम से ही जाना जाता था, जिसे औपनिवेशिक दौर और प्रशासनिक बदलावों के साथ 'केरल' कहा जाने लगा।

राज्य में नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई स्थानीय संगठनों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि मौजूदा नाम 'केरल' स्थानीय भाषा और संस्कृति से पूरी तरह मेल नहीं खाता, जबकि 'केरलम' शब्द सीधे-सीधे मलयालम परंपरा से जुड़ा है।

भ्रष्टाचार जांच पर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद अफसरों की पूर्व मंजूरी की शर्त पर बड़ी बहस

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेने की शर्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गहरी संवैधानिक बहस सामने आ गई है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 में जोड़ी गई धारा 17ए की वैधता पर खंडित फैसला सुनाया। पीठ में शामिल दोनों न्यायाधीश इस अहम मुद्दे पर एक राय नहीं बना सके। इसी कारण अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि बड़ी पीठ का गठन कर अंतिम और निर्णायक फैसला किया जा सके। यह निर्णय न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि ईमानदार अफसरों की सुरक्षा और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

दरअसल, केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए धारा 17ए जोड़ी थी। इस प्रावधान के तहत किसी भी लोकसेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दिए गए फैसलों, सिफारिशों या आदेशों के संबंध में जांच या पूछताछ शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। सरकार का तर्क था कि इस प्रावधान का मकसद ईमानदार अधिकारियों को बेवजह की जांच और उत्पीड़न से बचाना है, ताकि वे बिना डर के फैसले ले सकें। लेकिन दूसरी ओर, इस धारा को भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करने वाला बताते हुए इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में दलील दी कि यह प्रावधान भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक ढाल बन गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि जांच की मंजूरी देने का अधिकार सरकार के पास है, इसलिए अक्सर राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से अनुमति नहीं दी जाती और गंभीर आरोपों के बावजूद जांच शुरू ही नहीं हो पाती। इससे भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही खत्म होती है और कानून का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

इस मामले में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपने अलग फैसले में धारा 17ए को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मूल उद्देश्य ही यह है कि लोकसेवकों के खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो सके। पूर्व मंजूरी की शर्त जांच प्रक्रिया को रोकती है और कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का माध्यम बन जाती है। जस्टिस नागरत्ना के अनुसार, किसी लोकसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करने के लिए पहले अनुमति लेना कानून की भावना के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच ही बाधित कर दी जाए, तो आगे की कानूनी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए उनके मत में धारा 17ए को समाप्त किया जाना चाहिए।

वहीं, जस्टिस संजय कुमार विश्वनाथन ने बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि धारा 17ए को पूरी तरह खत्म करना ऐसा होगा जैसे बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक देना। उनके अनुसार, यह प्रावधान प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जरूरी सुरक्षा कवच है। उन्होंने माना कि ईमानदार अधिकारियों को अक्सर डर रहता है कि बाद में उनके फैसलों को लेकर उन्हें जांच और मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वे जोखिम लेने से बचते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि धारा 17ए संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते कि जांच की मंजूरी देने का अधिकार लोकपाल या राज्य स्तर पर लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्थानों के पास हो। इससे एक ओर ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और दूसरी ओर भ्रष्ट लोगों को बचाने की गुंजाइश भी कम होगी।

संपादकीय

जानलेवा सड़कें

देश में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार और समाज के स्तर पर चिंताएं तो व्यक्त की जाती हैं लेकिन इन्हें रोकने के लिये कारगर उपाय सिरे चढ़ते नजर नहीं आते। इस बारे में बार-बार वायदे किए जाते हैं, वहीं सुधार के लिये टुकड़ों-टुकड़ों में हस्तक्षेप किया जाता है। फलतः परिणाम वही ढाक के तीन पात रहता है। यह आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हर साल 1.6 लाख से अधिक मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। विडंबना देखिए कि किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के मुकाबले सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा लोगों की जान ले लेती हैं। हाल ही में सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के लिये किए गए सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2023 व 2024 में 100 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं पर किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम छह बजे से रात नौ बजे तक समय सड़क हादसों के लिये सबसे घातक होता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिये 18 सड़क गलियारों की पहचान की गई है, जिनमें सर्वेक्षण अवधि में सबसे अधिक मौते हुई थीं। इसके साथ ही दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील सौ जिलों में ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य पहल है। यह जानते हुए कि दुर्घटना रोकने के लिये सामान्य सलाह और एक समान नीतियां लक्ष्य हासिल करने में विफल रही हैं। यकीनी तौर पर दुर्घटना उन्मुख क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप बदलाव लाने के लिये बेहतर दृष्टिकोण साबित हो सकता है। बहुत संभव है कि एक खराब ढंग से डिजाइन किया गया मोड़, सड़क पर पर्याप्त रोशनी का न होना, प्रवर्तन में शिथिलता तथा ड्राइविंग में लापरवाही की आदतें, किसी क्षेत्र या जिला विशेष में सड़क दुर्घटनाओं की वजह हो सकती है। निश्चित तौर पर उच्च मृत्यु दर वाले गलियारों का मानचित्रण अधिकारियों को, उन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सुधार, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया बल तैनात करने में सहायक हो सकता है।

निस्संदेह, साक्ष्य और अतीत के अनुभव बताते हैं कि लक्षित प्रवर्तन बेहतर परिणाम दे सकता है। बंगलुरू का अनुभव बताता है कि लक्षित प्रयासों से वहां लगातार दूसरे वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के बावजूद मृत्यु दर में कमी आई है। जो इन प्रयासों की सार्थकता को दर्शाता है। निस्संदेह, अन्य शहरों को भी डेटा आधारित पुलसिंग, सीसीटीवी निगरानी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिये इस मॉडल को अपनाना होगा। इसमें दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की योजना तभी सफल होगी, जब वह पहचान और प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर काम करे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी पिछली कोशिशें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल न होने से विफल रही हैं। इन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये निरंतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के साथ ही परिणामों का नियमित ऑडिट करना आवश्यक है। इस बाबत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिए। वैसे सिर्फ राजमार्गों पर ही ध्यान केंद्रित करने के भी कई खतरे हैं। यह जानते हुए कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का मुश्किल से 2 से तीन प्रतिशत हिस्सा ही है। लेकिन ट्रैफिक की गति की तीव्रता के चलते इन पर होने वाली मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है। साल 2025 की पहली छमाही ही में करीब छब्बीस हजार से अधिक मौतें हुई हैं। वास्तव में शहरी सड़कें, जहां पैदल यात्री,साइकिल चालक और दोपहिया वाहन चालकों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का बड़ा हिस्सा है, वे अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं। इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिये निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित डिजाइन तैयार करने, वाहनों की गति का प्रबंधन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट बांधना सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन देखभाल व्यवस्था को साथ-साथ लागू करने की भी आवश्यकता है।

बच्चों को जीवंत दुनिया से जोड़ने की दिशा में पहल

> "डिजिटल युग में बच्चों द्वारा स्कूलों में समाचारपत्र पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय बदलावकारी कदम साबित हो सकता है। यदि वे रोज 10 मिनट भी समाचार पत्र पढ़ें, तो वर्षों में यह आदत उनके व्यक्तित्व, कैरियर और दृष्टिकोण को बदल सकती है। वहीं यह पहल बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने की स्क्रीन टाइम कम करने में सहायक होगी।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में समाचारपत्र पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरा है। दिसंबर, 2025 में उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद कम से कम 10 मिनट समाचार पत्र वाचन अनिवार्य कर दिया गया। इसके एक सप्ताह बाद, जनवरी 2026 की शुरुआत में राजस्थान में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया। जिसमें सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान 10 मिनट का विशेष सत्र समाचार पत्र पढ़ने के लिए तय किया गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में नियमित पढ़ने की आदत विकसित करना, उनकी शब्दावली समृद्ध करना, सामान्य ज्ञान बढ़ाना और समसामयिक घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब डिजिटल युग में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और स्क्रीन-आधारित सामग्री ने बच्चों का अधिकांश समय छीन लिया है। गहराई से पढ़ने की क्षमता व ध्यान केंद्रित करने की अवधि घट रही है और भाषा कौशल में कमी आ रही है। ऐसे में समाचार पत्र जैसी मुद्रित सामग्री को अनिवार्य बनाना बच्चों को स्क्रीन से दूर कर वास्तविक जानकारी के संपर्क में लाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में इस आदेश के अनुसार, स्कूलों की लाइब्रेरी में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे तथा प्रार्थना के बाद विद्यार्थी बारी-बारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल समाचार और संपादकीय पढ़कर सुनाएंगे। राजस्थान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई, जहां उच्च माध्यमिक व अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में न्यूनतम एक हिंदी व एक अंग्रेजी अखबार तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में दो हिंदी अखबार जरूरी हैं। इनकी सदस्यता का खर्च राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा वहन किया जाएगा।

इस पहल के सबसे प्रमुख प्रभावों में से एक है भाषा कौशल और शब्दावली में सुधार। समाचार पत्रों में इस्तेमाल होने वाली भाषा औपचारिक, विविध और समृद्ध होती है। बच्चे रोजाना नए शब्दों, मुहावरों और वाक्य संरचनाओं से परिचित होते हैं। राजस्थान के आदेश में कहा गया है कि प्रतिदिन 5 नए शब्दों का चयन कर उन्हें समझाया जाएगा, जिससे छात्रों का शब्द भंडार लगातार बढ़ेगा। यह न केवल हिंदी या अंग्रेजी की परीक्षाओं में मदद करेगा, बल्कि बोलचाल, लेखन और संवाद कौशल भी मजबूत करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, मुद्रित सामग्री पढ़ने से आंखों की गति, समझने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की अवधि में सुधार आता है, जो डिजिटल स्क्रीन पर संभव नहीं होता।

दूसरा अहम प्रभाव सामान्य ज्ञान और समसामयिक जागरूकता में वृद्धि है। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, राज्य लोक सेवा आयोग और यहां तक कि बोर्ड परीक्षाओं में भी करेंट अफेयर्स का बड़ा हिस्सा होता है। समाचारपत्र नियमित पढ़ने से बच्चे देश-विदेश की घटनाओं, नीतियों, आर्थिक बदलावों, पर्यावरण मुद्दों और वैज्ञानिक प्रगति से जुड़ते हैं। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है और वे समाज के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। मसलन जब कोई छात्र रोजाना संपादकीय पढ़ता है, तो उसकी विभिन्न मुद्दों पर तर्कपूर्ण सोच विकसित होती है, जो आलोचनात्मक चिंतन की नींव है।

तीसरा, यह कदम पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों के सरकारी स्कूलों में अक्सर बच्चों के घर समाचार पत्र नहीं पहुंचते। कई परिवारों में आर्थिक तंगी या पढ़ने की परंपरा न होने के कारण बच्चे किताबों और अखबारों से दूर रहते हैं। स्कूलों में इसे अनिवार्य करने से हर बच्चे को समान अवसर मिलेगा। शिक्षाविदों का कहना है कि यदि यह आदत बचपन से ही बन जाए, तो वयस्क होने पर भी व्यक्ति समाचार पत्र या किताबें पढ़ना जारी रखता है, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, यह पहल स्क्रीन टाइम को कम करने में भी सहायक होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों में ध्यान की कमी, नींद संबंधी समस्याएं, शारीरिक निष्क्रियता और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। समाचार पत्र पढ़ना एक शांत, गहन और एकाग्रता वाली गतिविधि है, जो डिजिटल डिटॉक्स का एक छोटा लेकिन प्रभावी रूप है।

हालांकि, दोनों राज्यों में इस निर्णय के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है कार्यान्वयन। ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्रों की समय पर डिलीवरी, शिक्षकों की कमी या उनकी ट्रेनिंग का अभाव, तथा स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का कम होना कार्य को कठिन बना सकता है। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी शुरू में इसे बोझ समझ सकते हैं, खासकर यदि वे हिंदी या अंग्रेजी में कमजोर हैं। तीसरा, समाचार पत्रों का कंटेंट हमेशा बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता। राजनीतिक खबरें, आपराधिक घटनाएं या संवेदनशील मुद्दे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को ये खबरें फिल्टर करने और सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।

चुनौतियों के बावजूद, यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया जाए तो इसका दूरगामी प्रभाव बहुत सकारात्मक होगा। भविष्य में अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाएं तो एक राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ने की संस्कृति मजबूत हो सकती है। यह बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें जीवंत दुनिया से जोड़ता है। यदि बच्चे रोजाना 10 मिनट भी समाचार पत्र पढ़ें, तो वर्षों में यह आदत उनके व्यक्तित्व, कैरियर और जीवन दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है।

प्रेरणा

पीड़ा को साधना बनाने वाला क्रांतिकारी

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक ऐसे क्षण छिपे हैं, जो केवल घटनाएं नहीं बल्कि चरित्र की पराकाष्ठा के उदाहरण हैं। अमर शहीद सुखदेव का जीवन भी ऐसे ही प्रसंगों से भरा हुआ था, जिनमें त्याग, संकल्प और असाधारण सहनशक्ति एक साथ दिखाई देती है। वे केवल अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, भय और दर्द को भी परास्त करने वाले योद्धा थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि क्रांति केवल नारे लगाने या बलिदान देने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को हर स्तर पर तपाने की प्रक्रिया है।

सुखदेव जिस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे, उसका नाम 'विलेजर' था। यह नाम उनके विचारों को दर्शाता था, क्योंकि वे क्रांति को केवल शहरों या पढ़े-लिखे वर्ग तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। गांव, किसान और सामान्य जनता को जोड़कर वे स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन बनाना चाहते थे। सुखदेव अपने दृढ़ निश्चय और हठ के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार किसी बात को मन में ठान लेने के बाद वे पीछे नहीं हटते थे, चाहे परिणाम कितना ही कष्टदायक क्यों न हो। यही स्वभाव आगे चलकर उनके जीवन के सबसे तीखे और असाधारण प्रसंगों में दिखाई देता है।

विद्यार्थी जीवन में सुखदेव ने अपने बाएं हाथ पर 'ओउम' और अपना नाम गुदवा लिया था। उस समय यह उनके आत्मविश्वास, आस्था और पहचान का प्रतीक रहा होगा। लेकिन जब वे फरारी के जीवन में प्रवेश कर चुके थे, तब यही निशान उनके लिए खतरे की घंटी बन गया। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों की पहचान के लिए हर छोटे संकेत पर नजर रखती थी। सुखदेव जानते थे कि यदि कभी पकड़े गए तो यह निशान उन्हें तुरंत पहचान में ला सकता है। इस समस्या का समाधान उन्होंने जिस तरीके से किया, वह साधारण सोच से बहुत आगे था।

आगरा में क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान बम बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड खरीदा गया था। यह एसिड कितना खतरनाक और जलन पैदा करने वाला होता है, इसका ज्ञान सुखदेव को था। फिर भी उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी सहनशक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बहुत-सा नाइट्रिक एसिड अपने हाथ पर बने 'ओउम' और अपने नाम पर डाल दिया। यह केवल पहचान मिटाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह जानने की एक कठोर कोशिश भी थी कि मनुष्य असहनीय पीड़ा को कितनी दूर तक सह सकता है।

कुछ ही समय में एसिड का असर दिखने लगा। जहां एसिड डाला गया था, वहां गहरे घाव बन गए। पूरा हाथ सूज गया, त्वचा जलने लगी और असह्य पीड़ा ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। शाम होते-होते तेज बुखार भी चढ़ आया। सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्थिति चीख-पुकार और घबराहट पैदा कर देने वाली होती, लेकिन सुखदेव ने अपनी पीड़ा का किसी से जिक्र तक नहीं किया। वे चुपचाप अपने काम में लगे रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। भीतर जलता हुआ दर्द उनके चेहरे पर नहीं झलका।

तीन दिन तक वे इसी हालत में रहे। दर्द, सूजन और बुखार उनके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। तीसरे दिन जब उन्होंने नहाने के लिए कमीज उतारी, तब भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद की नजर उनके जख्मों पर पड़ी। यह दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सुखदेव इतनी गंभीर हालत में भी चुप रह सकते हैं। उन्हें इस बात पर गहरा आक्रोश हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी पीड़ा को छिपाकर रखा। साथियों की नाराजगी में चिंता और प्रेम दोनों शामिल थे।

सुखदेव ने उनकी नाराजगी को हल्के हास्य में बदल दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि अब पहचान भी मिट जाएगी और यह भी अनुभव हो गया कि एसिड में कितनी जलन होती है। यह वाक्य उनके विचारों की गहराई को दर्शाता है। उनके लिए पीड़ा केवल कष्ट नहीं थी, बल्कि अनुभव और तैयारी का साधन थी। वे हर दर्द को आने वाले संघर्ष की भूमिका मानते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति पीड़ा से डर गया, वह बड़े उद्देश्य के लिए खड़ा नहीं हो सकता।

इसके बाद भी सुखदेव उसी अवस्था में आगरा में चार-पांच दिन तक रहे। जख्म खुले थे, हाथ सूजा हुआ था और शरीर कमजोर पड़ रहा था। सभी साथियों ने उनसे बार-बार आग्रह किया कि वे दवा लें, मलहम लगवाएं और पट्टी कराएं। लेकिन सुखदेव ने किसी की बात नहीं मानी। उनका विश्वास था कि जब तक शरीर साथ दे रहा है, तब तक क्रांतिकारी का कर्तव्य काम करते रहना है। वे बैठकों में शामिल होते रहे, योजनाओं पर चर्चा करते रहे और आंदोलन की जिम्मेदारियों को निभाते रहे।

अंततः वे बिना किसी इलाज के अगले मिशन के लिए लाहौर रवाना हो गए। यह घटना सुखदेव के व्यक्तित्व को एक असाधारण ऊंचाई पर ले जाती है। वे केवल हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे स्वयं पर अनुशासन और नियंत्रण की चरम सीमा तक जाने वाले साधक थे। उनकी सहनशक्ति हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी शत्रु से लड़ने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए अपने भीतर की कमजोरियों, भय और दर्द से भी युद्ध करना पड़ता है। सुखदेव का यह जीवन प्रसंग आज भी हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची क्रांति पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेती है और वहीं से इतिहास का मार्ग बदलती है।

Gen Z को लेकर PM Modi का बयान सही है या Manish Tewari की चिंता सही है?

देश की राजनीति में इन दिनों जेन जी को लेकर एक वैचारिक घमासान तेज हो गया है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो जेन जी को भारत के भविष्य का वाहक बताते हुए उनसे मानसिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का आह्वान कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हैं जो एशिया के कई देशों में जेन जी के नेतृत्व में हुए हालिया प्रदर्शनों को चेतावनी की तरह देखते हैं और उसके गहरे निहितार्थों की बात करते हैं हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए साफ कहा कि जेन जी का सबसे बड़ा दायित्व देश को दासता की मानसिकता से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल नहीं बल्कि सोच की आजादी का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार रहा है जहां अपनी क्षमताओं पर संदेह किया गया और विदेशी मानकों को ही श्रेष्ठ माना गया। मोदी ने कहा कि आज का युवा उस दौर को नहीं जानता जब नीतिगत पंगुता और निर्णयहीनता ने देश की गति को थाम रखा था लेकिन यही युवा अब उस सोच को हमेशा के लिए दफन कर सकता है। प्रधानमंत्री ने जेन जी को आत्मनिर्भर भारत का असली सिपाही बताते हुए कहा कि स्टार्टअप संस्कृति, तकनीक आधारित नवाचार, अंतरिक्ष विज्ञान और डिजिटल भारत जैसी पहलों में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। उनका जोर इस बात पर था कि जेन जी को केवल विरोध की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि समाधान और सृजन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत का युवा अगर अपनी जड़ों और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से जुड़ता है तो वह वैश्विक मंच पर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसके विपरीत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का नजरिया कहीं अधिक सतर्क और चिंतित दिखाई देता है। उन्होंने हाल के महीनों में एशिया के कई देशों में जेन जी के नेतृत्व में हुए आंदोलनों का हवाला देते हुए कहा कि इन प्रदर्शनों को सिर्फ युवा आक्रोश कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तिवारी ने कहा कि इन आंदोलनों ने कई जगह सरकारों को हिला दिया और कहीं कहीं सत्ता परिवर्तन तक का कारण बने। उनका कहना है कि यह समझना जरूरी है कि ये आंदोलन केवल स्थानीय असंतोष का परिणाम नहीं हैं बल्कि इनके पीछे वैश्विक राजनीतिक प्रवृत्तियां और डिजिटल माध्यमों की बड़ी भूमिका है। मनीष तिवारी ने आगाह किया कि सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क के जरिये जेन जी तेजी से संगठित होती है और भावनात्मक मुद्दों पर उग्र प्रतिक्रिया देती है। यह शक्ति जितनी रचनात्मक हो सकती है उतनी ही विनाशकारी भी साबित हो सकती है अगर इसे विवेकपूर्ण दिशा न मिले। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अन्य एशियाई देशों के अनुभवों से सबक लेना चाहिए जहां युवा आंदोलनों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव डाला और अस्थिरता पैदा की।

देखा जाये तो दुनिया भर में जेन जी के आंदोलनों ने एक नया राजनीतिक पैटर्न गढ़ा है। ये आंदोलन तेज हैं भावनात्मक हैं और डिजिटल प्लेटफार्म के सहारे सीमाओं को लांघते हैं। लेकिन भारत का संदर्भ अलग है। यहां का जेन जी सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता, संविधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक परंपराओं के बीच पला बढ़ा है। यही कारण है कि भारतीय जेन जी को केवल वैश्विक आंदोलनों की नकल करने वाला नहीं बल्कि अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने वाला माना जा रहा है। मोदी और मनीष तिवारी के बयानों के बीच की टकराहट असल में इस सवाल पर आकर टिक जाती है कि युवा शक्ति को प्रेरणा की जरूरत है या नियंत्रण की। मोदी जहां युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना भरना चाहते हैं वहीं मनीष तिवारी इस चेतना को विवेक और सावधानी के साथ देखने की बात करते हैं। हालांकि दोनों ही यह मानते हैं कि जेन जी अब हाशिये पर नहीं बल्कि राजनीति और समाज के केंद्र में है। देखा जाये तो जेन जी को लेकर चल रही यह बहस भारत के भविष्य की बहस है। प्रधानमंत्री मोदी की बातों में एक स्पष्ट संदेश है कि युवा केवल शिकायत करने वाली पीढ़ी न बने बल्कि देश की दिशा बदलने वाली शक्ति बने। दासता की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान दरअसल आत्मविश्वास और स्वदेशी सोच की पुकार है। वहीं मनीष तिवारी की चेतावनी यह याद दिलाती है कि ऊर्जा अगर दिशा विहीन हो जाए तो वह रचनात्मक कम और विध्वंसक अधिक हो सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और मनीष तिवारी के बीच चल रही जेन जी को लेकर बहस के समानांतर राहुल गांधी भी युवाओं से संवाद की अपनी अलग रणनीति के कारण चर्चा में रहे हैं। हाल के दिनों में जेन जी के साथ उनकी अनौपचारिक बातचीत के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं जिनमें वे कॉलेज जीवन, प्रेम प्रसंगों, व्यक्तिगत पसंद और युवाओं की रोजमर्रा की चिंताओं पर खुलकर बात करते दिखाई देते हैं। यह संवाद कई बार गंभीर राजनीति से ज्यादा मीम संस्कृति का हिस्सा बन गया। दरअसल, कांग्रेस की रणनीति के तहत यह प्रयास जेन जी को सीधे संबोधित करने और उन्हें लोकतंत्र, संविधान और चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने का है। राहुल गांधी बार बार युवाओं से अपील करते रहे हैं कि वह केवल दर्शक न बनें बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं खासकर रोजगार, भ्रष्टाचार और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर। उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिये जिन्हें जेन जी को उकसाने के तौर पर देखा गया। हालांकि यह साफ दिख रहा है कि जेन जी केवल राजनीतिक संदेश सुनने वाला वर्ग नहीं है बल्कि वह खुद विमर्श की दिशा तय करने लगा है।

अभियान

मां कामाख्या की साधना से जीवन की हर उलझन का समाधान

भारतीय सनातन परंपरा में शक्ति की उपासना को सृष्टि की मूल चेतना से जुड़ने का मार्ग माना गया है और इसी शक्ति परंपरा में मां कामाख्या का स्थान अत्यंत रहस्यमय, प्रभावशाली और सिद्धिदायक माना गया है। मां कामाख्या को केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि इच्छा, संकल्प और सृजन की आद्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि संसार में जो भी इच्छा जन्म लेती है, उसका बीज मां कामाख्या की चेतना में निहित होता है। यही कारण है कि उन्हें कामना पूर्ति की देवी कहा गया है और उनकी साधना को जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान माना जाता है। असम की नीलाचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित कामाख्या मंदिर न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व में तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है और यह 51 शक्तिपीठों में एक अत्यंत जाग्रत शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है।

मां कामाख्या का स्वरूप अन्य देवी मंदिरों से भिन्न है। यहां किसी प्रतिमा की पूजा नहीं होती, बल्कि देवी की योनि स्वरूप शक्ति की आराधना की जाती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन, पोषण और परिवर्तन का प्रतीक है। यह स्वरूप यह संदेश देता है कि शक्ति केवल विनाश नहीं, बल्कि जीवन के निरंतर प्रवाह की आधारशिला है। मां कामाख्या की उपासना करने वाला साधक केवल बाहरी इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपी चेतना और ऊर्जा को भी जागृत करता है। यही कारण है कि उनकी साधना को जीवन परिवर्तन की साधना कहा गया है।

तंत्र शास्त्र में मां कामाख्या को विशेष महत्व प्राप्त है। उन्हें दस महाविद्याओं की गुप्त शक्ति से भी जोड़ा जाता है और माना जाता है कि उनकी कृपा से साधक को गूढ़ ज्ञान, आत्मिक बल और इच्छाशक्ति की अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। मां कामाख्या की साधना में मंत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उनके मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि कंपन हैं, जो साधक के मन, शरीर और ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ इन मंत्रों का जाप करता है, तो धीरे-धीरे उसके जीवन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है।

मां कामाख्या का प्रणाम मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना गया है — "कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरि हरप्रिये। कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥" यह मंत्र साधक को मां के समक्ष पूर्ण समर्पण की अवस्था में ले जाता है। इसमें साधक अपनी सभी इच्छाएं, भय और अपेक्षाएं देवी के चरणों में अर्पित कर देता है। इसी के साथ बीज मंत्र "क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः" को तंत्र परंपरा में अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। 'क्लीं' बीज को आकर्षण, प्रेम, सृजन और चेतना जागरण का बीज कहा गया है। जब यह बीज मां कामाख्या के नाम के साथ जुड़ता है, तो यह साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। मां कामाख्या के मंत्र जाप की विधि में शुद्धता, अनुशासन और निरंतरता का विशेष महत्व है। साधक को प्रतिदिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर शांत वातावरण में बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले मां का स्मरण करते हुए उनसे कृपा, मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम तीन माला मंत्र जाप करने की परंपरा मानी जाती है। यदि कोई साधक लगातार 41 दिनों तक नियमपूर्वक इस साधना को करता है, तो उसके जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कई साधकों का अनुभव रहा है कि इस अवधि के बाद उनके भीतर एक अलग प्रकार की शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है।

मां कामाख्या के मंत्र जाप का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के आकर्षण और व्यक्तित्व पर पड़ता है। यह आकर्षण केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति की वाणी, विचार और व्यवहार में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। लोग स्वतः ही ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और जो रिश्ते तनाव या गलतफहमी से गुजर रहे होते हैं, उनमें भी संतुलन आने लगता है। यही कारण है कि प्रेम, विवाह और दांपत्य जीवन की समस्याओं से जूझ रहे लोग मां कामाख्या की साधना को अत्यंत प्रभावी मानते हैं।

इसके साथ ही मां कामाख्या के मंत्र का प्रभाव व्यक्ति की रचनात्मकता और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। मंत्र जाप से मन की चंचलता कम होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। जो लोग अपने करियर, व्यवसाय या पढ़ाई में बार-बार रुकावटों का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें इस साधना से नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक केंद्रित हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार होता है। यह साधना आलस्य, भ्रम और मानसिक थकान को दूर करने में भी सहायक मानी जाती है।

मां कामाख्या की कृपा से आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। नियमित मंत्र जाप करने से भय, संदेह और नकारात्मक सोच धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। व्यक्ति स्वयं को भीतर से मजबूत महसूस करने लगता है और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ करता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी अनुभव किया जाता है, जहां साधक अपने अस्तित्व को अधिक गहराई से समझने लगता है।

तंत्र साधना के मार्ग में मां कामाख्या को सिद्धिदात्री माना गया है। उनकी साधना से साधक को तंत्र मार्ग में सफलता प्राप्त होती है और वह देवी की दिव्य शक्तियों से जुड़ने लगता है। हालांकि यह मार्ग अत्यंत संयम और शुद्ध भाव की मांग करता है, क्योंकि तंत्र साधना केवल इच्छापूर्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी है। मां कामाख्या की कृपा से साधक अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानता है और उनका सदुपयोग करना सीखता है।

सबसे महत्वपूर्ण विश्वास यह है कि मां कामाख्या के मंत्र जाप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यहां यह समझना आवश्यक है कि देवी साधक को वही देती हैं, जो उसके जीवन के लिए वास्तव में आवश्यक होता है। कई बार व्यक्ति जिन इच्छाओं को लेकर साधना करता है, देवी उसे उनसे भी श्रेष्ठ मार्ग प्रदान कर देती हैं। इस प्रक्रिया में साधक का दृष्टिकोण बदलने लगता है और वह जीवन को अधिक सकारात्मक, संतुलित और जागरूक दृष्टि से देखने लगता है।

इस प्रकार मां कामाख्या की साधना केवल किसी एक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जीवन के संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया है। उनकी कृपा से व्यक्ति नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि मां कामाख्या को केवल कामनाओं की देवी नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली आद्य शक्ति माना गया है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत, बच्चों को छुट्टी देकर सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने उड़ाया चिकन-शराब का जश्न

(जीएनएस)। सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा को संस्कार और अनुशासन का केंद्र माने जाने वाले सरकारी विद्यालय में खुद हेडमास्टर की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला गंगापुर सिटी क्षेत्र के हिंगोटिया गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल खुलने के पहले ही दिन हेडमास्टर ने बच्चों की छुट्टी कर स्कूल परिसर को निजी मौज-मस्ती का अड्डा बना दिया।

जानकारी के अनुसार, शीतकालीन अवकाश और कड़ाके की ठंड के बाद सोमवार को ही स्कूल दोबारा खुले थे। स्कूल में करीब 31 बच्चे नामांकित हैं और कुल चार शिक्षकों का स्टाफ स्वीकृत है। लेकिन पहले ही दिन हेडमास्टर अमर सिंह मीणा ने दोपहर करीब ढाई बजे सभी बच्चों को छुट्टी दे दी। बच्चों के घर जाने के बाद स्कूल की रसोई में गैस चूल्हा जलाया गया और वहां नॉनवेज पार्टी की तैयारी शुरू कर दी गई। स्कूल की रसोई में चिकन पकाया जा रहा था और साथ में टिक्कड़ भी सेके जा रहे थे।

गांव में जब यह खबर फैली कि स्कूल में बच्चों को समय से पहले छुट्टी देकर कुछ गड़बड़ की जा रही है, तो कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने जो दृश्य देखा, उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। स्कूल परिसर में रसोई के पास चिकन और टिक्कड़ बनाए जा रहे थे, जबकि स्कूल मैदान में हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर धूप सेंकते नजर आए। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया और सवाल पूछे, तो हेडमास्टर का रवैया और भी

चौंकाने वाला रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हेडमास्टर ने बेपरवाह अंदाज में कहा, "जो चाहे कर लो, जहां चाहे शिकायत कर लो।"

ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें स्कूल की रसोई में पकता चिकन, चूल्हे पर टिक्कड़ और नशे की हालत में मौजूद हेडमास्टर साफ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल भी उठने लगे कि जब स्कूल खुले ही थे, तो बच्चों को इतनी जल्दी क्यों छुट्टी दी गई और स्कूल को निजी पार्टी स्थल में कैसे बदला गया।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में उस समय बाकी शिक्षक मौजूद नहीं थे। जब हेडमास्टर से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने लापरवाही भरे लहजे में जवाब दिया कि दो शिक्षक बीएलओ ड्यूटी पर हैं और एक शिक्षक छुट्टी पर है, जबकि वह खुद स्कूल में मौजूद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर इस तरह की हरकत करना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।

मामला सामने आने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गायत्री वरमेंदू ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस टीम में हिंगोटिया, रेती और सपेरा बस्ती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों को शामिल किया गया है। टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपे।

इधर, गांव के लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल पहले ही संसाधनों और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में यदि हेडमास्टर ही इस तरह अनुशासन तोड़ेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई और भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। ग्रामीणों ने हेडमास्टर अमर सिंह मीणा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है और कहा है कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उच्च अधिकारियों तक शिकायत लेकर जाएंगे।

यह मामला केवल एक स्कूल या एक हेडमास्टर तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त लापरवाही और जवाबदेही की कमी के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वालों पर वास्तव में कितनी सख्ती बरती जाती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के प्रकाश मनोदिव्यांग स्कूल का दौरा किया

- मुख्यमंत्री ने आत्मीय संवेदना और परिवार के बड़े-बुजुर्ग की तरह वात्सल्य व स्नेह भाव से स्कूल के बच्चों को मिठाई बांटकर उन्हें उत्तरायण की शुभकामनाएं दीं
- मनोदिव्यांग बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति
- मुख्यमंत्री ने अमेरिका की यूनिफाइड बास्केटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक सहित स्पेशल खेल महाकुंभ के विजेता बच्चों को सम्मानित किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के बोड़कदेव क्षेत्र में स्थित प्रकाश मनोदिव्यांग निवासी शाला का दौरा किया और स्कूल की विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने मनोदिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देने के कार्य की तुलना उत्तम सेवा के साथ की।

मुख्यमंत्री उत्तरायण से पूर्व मंगलवार सुबह बोड़कदेव स्थित इस मनोदिव्यांग स्कूल में पहुंचे। उन्होंने परिवार के किसी बड़े-बुजुर्ग की तरह वात्सल्य व स्नेह भाव से मनोदिव्यांग बच्चों को मिठाई वितरित कर उन्हें उत्तरायण पर्व की शुभकामनाएं दीं। मनोदिव्यांग बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने संस्था के कार्यों की भी सराहना की, जिसके अंतर्गत मनोदिव्यांग बच्चों को दैनिक और सामाजिक जीवन के कार्यों को करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

संस्था की ट्रस्टी डॉ. सुजाताबेन शाह ने संस्था की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था की स्थापना से लेकर अब तक कुल 1500 से अधिक बच्चों ने इस स्कूल में पढ़ाई की है। वर्तमान में लगभग 100 बच्चों को अक्षरों, रंगों और आकृतियों को पहचानने के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे विभिन्न खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गत महीने अमेरिका के प्यूर्टो रिको में आयोजित यूनिफाइड ओलंपिक बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्कूल के हित सावंत नाम के विद्यार्थी ने कांस्य पदक जीता है। जबकि, कुल 27 विद्यार्थियों ने जिला और राज्य स्तर पर स्पेशल खेल महाकुंभ में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति भी दी।

इस दौरान उप महापौर श्री जतिनभाई पटेल, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी सहित गणमान्य लोग और संस्था के न्यासी, शिक्षक आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की भारत – गुजरात यात्रा संपन्न

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी भावपूर्ण विदाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की भारत- गुजरात यात्रा मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। श्री मर्ज ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रणनीतिक कार्यक्रमों में तथा भारत-जर्मन सीईओ फोरम में सहभागिता करने के बाद मंगलवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से जर्मनी के लिए प्रस्थान किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित महानुभावों ने जर्मन चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज को भावपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, शहर पुलिस आयुक्त श्री जी. एस. मलिक, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी, जिला कलेक्टर सुजीत कुमार, विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

करूर त्रासदी की परछाइयाँ दिल्ली तकः भगदड़ मामले में एक्टर विजय से फिर पूछताछ, सियासी और कानूनी दबाव तेज

(जीएनएस)। नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में हुई भीषण भगदड़ की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है और इस मामले में टीवीके प्रमुख व मशहूर अभिनेता विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच के सिलसिले में विजय को 19 जनवरी को दोबारा दिल्ली बुलाया है। इससे पहले भी उनसे लंबी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, करीब छह घंटे तक चली पिछली पूछताछ में सीबीआई ने रैली के आयोजन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और कार्यक्रम से जुड़े निर्णयों को लेकर विस्तार से सवाल किए थे। यह भगदड़ 27 सितंबर को करूर में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान हुई थी, जहां हजारों की संख्या में लोग विजय को देखने और सुनने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान अचानक हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई, जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती दौर में इस मामले की जांच को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और अलग-अलग एजेंसियों को जांच सौंपी गई, लेकिन संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आ सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग को रद्द करते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संवेदनशील मामले की जांच की निगरानी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा की जानी चाहिए, ताकि

किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव की गुंजाइश न रहे। इसके बाद से ही सीबीआई ने मामले की परत-दर-परत जांच शुरू की है।

सीबीआई की जांच का फोकस मुख्य रूप से इस बात पर है कि कार्यक्रम के आयोजन में किस स्तर पर चूक हुई, भीड़ नियंत्रण के लिए क्या इंतजाम किए गए थे और आयोजन से जुड़े लोगों ने सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई थी। जांच एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या रैली के आयोजन में तय मानकों और नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इसी कड़ी में विजय से बार-बार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम का सीधा संबंध उनकी पार्टी और उनके सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था।

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी हादसे के कारणों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी। तमिलनाडु पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया था कि कार्यक्रम स्थल पर विजय के पहुंचने में कथित तौर पर काफी देरी हुई, जिससे वहां मौजूद भीड़ में नाराजगी फैल गई और हालात बेकाबू हो गए। पुलिस का यह भी कहना था कि पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति बनी। हालांकि इन आरोपों को विजय ने सिरे से खारिज करते हुए इसे सत्ताधारी डीएमके की साजिश करार दिया था। डीएमके ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

अब जब मामला सीबीआई के हाथ में है, तो जांच की दिशा और तेज हो गई है। सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रशासन से किस तरह की अनुमति ली गई थी, सुरक्षा एजेंसियों के साथ क्या समन्वय था और आयोजकों की ओर से किन निर्देशों का पालन किया गया। 19 जनवरी को होने वाली अगली पूछताछ को इस मामले में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हुई पूछताछ के आधार पर एजेंसी कई नए सवालों और दस्तावेजों के साथ विजय से दोबारा जवाब तलब कर रही है।

करूर भगदड़ की जांच अब सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं रह गई है, बल्कि यह राजनीतिक जवाबदेही, सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन जैसे बड़े मुद्दों से भी जुड़ गई है। 41 लोगों की मौत ने इस त्रासदी को और भी संवेदनशील बना दिया है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं सीबीआई की कार्रवाई और विजय से बार-बार पूछताछ यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

करुणा अभियान - 2026

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने करुणा अभियान के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का दौरा किया

- उत्तरायण में पतंग-डोर से घायल होने वाले पक्षियों को बचाने और उनके उपचार के लिए पूरे राज्य में लगभग 728 वेटरनरी चिकित्सक, 8620 सेवाभावी स्वयंसेवक सेवारत, राज्य भर में 1036 उपचार केंद्र और कलेक्शन सेंटर बनाए गए
- पक्षी उपचार केंद्रों की जानकारी 8320002000 नंबर पर वॉट्सऐप द्वारा और वेबसाइट पर हासिल की जा सकती है
- 2017 से शुरू हुए करुणा अभियान के तहत कुल 1.12 लाख पशु-पक्षियों का रेस्क्यू हुआ

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उत्तरायण पर्व के दौरान पतंग की डोर पक्षियों को घायल होने से बचाने और घायल पक्षियों के उपचार के लिए चल रहे राज्यव्यापी करुणा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया के साथ अहमदाबाद के बोड़कदेव क्षेत्र में कार्यरत वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और वाटर बर्ड्स सेंटर का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख डॉ. ए.पी. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तरायण पर्व में घायल पक्षियों को बचाने का यह अभूतपूर्व अभियान है। इस अभियान में अब तक हजारों घायल पक्षियों की जान बचाई गई है। 10 से 20 जनवरी के दौरान चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए पशुपालन विभाग, वन विभाग, महानगर पालिकाएं और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थान सहभागी बने हैं।

करुणा अभियान-2026 के अंतर्गत लगभग 728 से अधिक वेटरनरी चिकित्सक और 8620 से अधिक सेवाभावी स्वयंसेवक सेवारत हैं। पूरे राज्य में कुल 1036 से अधिक उपचार केंद्र और कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए हैं। इस अभियान के दौरान राज्यभर में पशु क्लीनिक, वेटरनरी पॉलिक्लीनिक और शाखा पशु क्लीनिकों के अलावा मोबाइल पशु क्लीनिक और करुणा एनीमल एंबुलेंस छुट्टी के दिन भी कार्यरत रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 से शुरू की गई इस करुणामय पहल के चलते अनेक मूक पशु-पक्षियों को नवजीवन मिला है। उत्तरायण जैसे त्योहारों और लोकोत्सवों के दौरान बेजुबान जीवों की चिंता कर उनके उपचार और देखभाल का यह करुणा अभियान गुजरात की अनूठी पहल बन गया है।

गत वर्ष करुणा अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 12,771 से अधिक पशु-पक्षियों

को रेस्क्यू किया गया था, जबकि पिछले 9 वर्षों में इस अभियान के तहत राज्य भर में 1,12,951 पशु-पक्षियों को रेस्क्यू किया है। जिनमें से 1,03,874 पशु-पक्षियों को उचित उपचार प्रदान कर बचा लिया गया।

गुजरात द्वारा सर्वप्रथम शुरू किए गए 'करुणा अभियान' का आदर्श मॉडल आज पूरे देश के लिए पथप्रदर्शक बन गया है।

उत्तरायण पर्व के दौरान पतंग की डोर से कोई बेजुबान पशु या पक्षी घायल न हो, इस बात की सतर्कता के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 10 से 20 जनवरी के दौरान राज्यव्यापी करुणा अभियान चलाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के किसी भी स्थल पर घायल पक्षियों को त्वरित और उचित उपचार प्रदान करने के लिए वन विभाग द्वारा वॉट्सऐप नंबर 8320002000 और हेल्पलाइन नंबर 1926 जारी किया गया है, जो चौबीसों घंटे सातों दिन कार्यरत रहेगा। इस वॉट्सऐप नंबर पर 'Hi' मेसेज मेसेज भेजने पर एक लिंक मिलेगी, जिस पर क्लिक करने से जिलेवार उपलब्ध सभी पक्षी उपचार केंद्रों की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, पशुपालन विभाग का 1962 नंबर भी सेवारत है। नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर मूक पशु-पक्षियों की जान बचा सकते हैं।

मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचनबेन, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांग दाणी, राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग के निदेशक सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी, करुणा अभियान से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवक और एनसीसी के कैडेट्स उपस्थित रहे।

रेल प्रशासन द्वारा जनता से पटरियों के ऊपर लगे हाई वोल्टेज तारों से सावधान रहने की अपील

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भावनगर रेलवे मंडल के सभी खंडों में रेलवे लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) तारें लगी हुई हैं, जो अत्यंत खतरनाक हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि पतंग उड़ाने के दौरान धागे (डोर) 25,000 वोल्ट की ओएचई तारों में उलझ जाते हैं। इससे रेल कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न हो जाता है। ट्रैक पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतने तथा किसी भी स्थिति में पतंग के धागों के संपर्क में न आने की अपील की गई है, क्योंकि इससे

विद्युत करंट लगने का गंभीर खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया है कि जनसाधारण रेलवे ट्रैक के समीप पतंग उड़ाते हैं और ओएचई तारों से फंसी पतंग निकालने का प्रयास करते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे रेलवे पटरी के पास पतंग उड़ाने से बचें तथा रेलवे के हाई वोल्टेज ट्रैक्शन तारों से किसी भी वस्तु को निकालने का प्रयास न करें। उन्होंने सामाजिक हित में इस महत्वपूर्ण संरक्षा संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की भी अपील की है।

रेल प्रशासन जनता की संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सहयोग की अपेक्षा करता है।

अहमदाबाद मंडल द्वारा रेलवे परिसर में थूकने एवं गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

12 जनवरी को 158 लोगों पर कार्रवाई, 23,950 का जुर्माना वसूला गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने तथा यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 198 एवं 167 के अंतर्गत 12 जनवरी 2026 को एक विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान अहमदाबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में कुल 158 मामलों में कार्रवाई की गई,

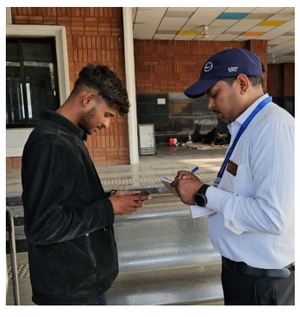

जिनसे 23,950 का जुर्माना वसूला गया। स्टेशन-वार विवरण इस प्रकार है—

- अहमदाबाद स्टेशनः 69 मामलों में 11,800
- साबरमतीः 13 मामलों में 1,400
- महेसाणाः 5 मामलों में 1,000
- पालनपुरः 17 मामलों में 2,500
- विरमगामः 6 मामलों में 750
- गांधीधामः 18 मामलों में 3,100

इसके अतिरिक्त Sr DCM SQD द्वारा 30 मामलों में 3,400 का जुर्माना लगाया गया। इस संपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर कुल 22 रेल कर्मचारियों की तैनाती कर सघन निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

रेल प्रशासन यात्रियों एवं आम जनता से अपील करता है कि रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में थूकने एवं गंदगी फैलाने से परहेज करें तथा स्वच्छता से संबंधित नियमों का पालन करें।

स्वच्छ रेलवे, सुरक्षित रेलवे के निर्माण में सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से अत्याधुनिक बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' लैब का शिलान्यास

▸▸ गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 362 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा राज्य सरकार संचालित देश का प्रथम 'बीएसएल-4' लैब

▸▸ गुजरात की धरती से भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बायो-सेफ्टी क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

▸▸ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की प्रेरक उपस्थिति

(जीएनएस)। गांधीनगर : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के प्रथम अत्याधुनिक बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' लैब तथा 'एनिमल बायो-सेफ्टी लेवल' सुविधा का गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में शिलान्यास किया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया भी उपस्थित रहे।

इस समारोह के दौरान गुजरात बायो-टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' सुविधा को भारत सरकार की 'बायोई3 नीति' अंतर्गत 'नेशनल सेंटर फॉर हाई कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च फैसिलिटी' के रूप में नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की धरती से भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बायो-सेफ्टी क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। पुणे के बाद देश का यह केवल दूसरा उच्च स्तरीय लैब है, लेकिन राज्य सरकार की विशेष पहल से 362 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह देश का पहला बीएसएल-4 लैब बनेगा। भविष्य में यह लैब जानलेवा वायरसों से लड़ने के लिए भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच तथा जैव-सुविधाओं का मजबूत किला सिद्ध होगा।

श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ होना चाहिए'; विजन को दोहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह लैब शोधकर्ताओं तथा युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोलेगा। विशेषकर पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'वन हेल्थ मिशन' को इस लैब से गति मिलेगी। हाल ही में गुजरात द्वारा झेले गए चांदीपुरा तथा लम्पी स्किन डिसीज जैसे संकटों के विरुद्ध इस प्रकार की रिसर्च आधारित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य थी।

भारत के बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन के आँकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2014 में भारत की बायो-इकोनॉमी, जो 10 बिलियन डॉलर थी, वर्ष 2024 तक बढ़कर 166 बिलियन डॉलर के पार पहुँची है। अनुसंधान को आविष्कार की आत्मा मानते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली ढाँचागत सुविधाओं के कारण आज भारत के वैज्ञानिक अत्यंत सुरक्षित वातावरण में विश्व स्तरीय शोध-अनुसंधान कर रहे हैं।

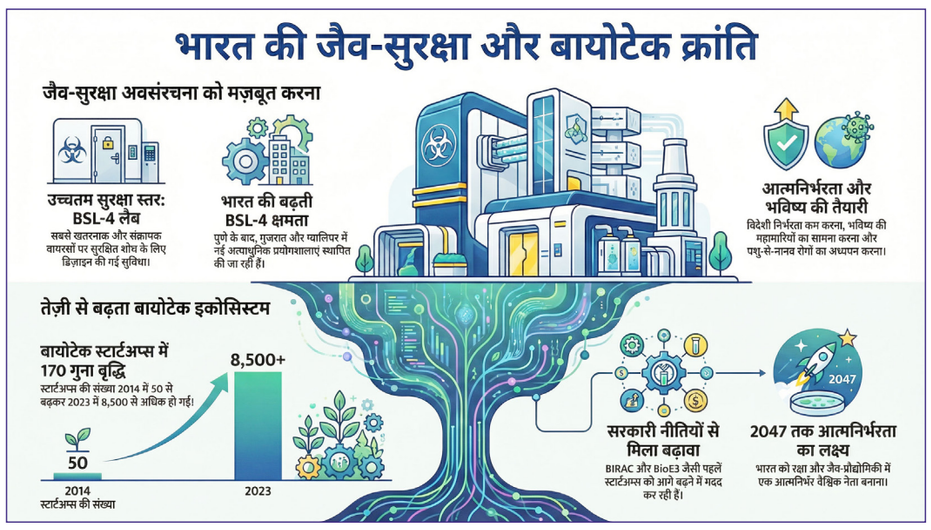

केन्द्रीय गृह मंत्री ने स्टार्टअप तथा निवेश क्षेत्र में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2014 में इस क्षेत्र में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जो आज 10,000 से अधिक हुए हैं। इसी प्रकार; इनक्यूबेटर्स की संख्या 6 से बढ़कर 95 और इनक्यूबेशन स्पेस 60 हजार स्क्वायर फीट से बढ़कर 9 लाख स्क्वायर फीट हुआ है। उल्लेखनीय रूप से; प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए तक पहुँचा है और पेटेंट फाइलिंग की संख्या भी 125 से बढ़कर 1300 को पार कर गई है, जो दर्शाता है कि भारत के युवा अब 'जॉब सीकर' नहीं, बल्कि 'जॉब गिवर' बने हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की 'बायोई3 नीति' अंतर्गत देश को बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अधिक ऊँचाई पर ले जाने का संकल्प है। भारत आज कोरोना तथा सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों की वैक्सीन का स्वदेशी निर्माण कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों तथा अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान किया कि भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। यह लैब आगामी समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम बनेगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज 'विज्ञान' तथा 'विरासत'; दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने अल्प समय में वैक्सीन बनाकर 140 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित करते हुए विश्व की सहायता की है, जिसकी नींव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ बनाने का दृष्टिकोण रहा है। इस लैब द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को अब सैंपल टेस्टिंग के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सिद्ध करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2027 तक सेमीकंडक्टर तथा बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर प्रथम पंक्ति में होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने एंटीबायो-टिक दवाइयों के दुरुपयोग से उत्पन्न हो रहे 'साइलेंट डिजास्टर' (एएमआर) को लेकर चिंता व्यक्त की और विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं का अनुसंधान द्वारा नई पीढ़ी को सुरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने बायो-टेक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल फैसिलिटी का अधिकतम उपयोग कर मानव जीवन के लिए उपयोगी फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन और वैक्सीन विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सुविधा केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभरेगी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जब देश 'विकसित भारत' की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब बायो-टेक्नोलॉजी जैसा विज्ञान हमें सुरक्षा देगा और 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' जैसी विरासत हमें गौरवपूर्ण पहचान देगी। भारत आज संस्कृति की नींव पर आधुनिक विज्ञान की इमारत खड़ी कर रहा है। बायो-टेक क्षेत्र में हुआ यह नया अनुसंधान देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने देश को संभावित महामारियों के विरुद्ध अधिक सुरक्षित बनाने वाले इस प्रकल्प को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हेल्थ केयर और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समय से आगे सोचने वाले विजनरी लीडर हैं। उनके ऐसे ही विजन के कारण हमने गुजरात बायो-टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) को कार्यरत कर वायरल रोगों, जेनेटिक संक्रमणों और महामारी जैसे गंभीर स्वास्थ्य क्षेत्रों के निदान अनुसंधान के लिए बाहरी संस्थाओं पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने बीएसएल-4 लैब के कार्यरत होने से हाई रिस्क वाले वायरस पर राज्य में अनुसंधान संभव होने से समय पर, सटीक और विश्वसनीय निदान उपलब्ध होने तथा स्वास्थ्य प्रणाली के अधिक सशक्त और सज्ज बनने का विश्वास व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीआरसी केवल एक अनुसंधान संस्थान ही नहीं, बल्कि राज्य की बायो-टेक कैपेसिटी का नोडल सेंटर भी है। इसकी भूमिका देते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएल-4 लैब में होने वाला अनुसंधान सीधे निदान, उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में परिवर्तित होने वाला ट्रांजिशनल रिसर्च बनेगा।

उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत@ 2047' के प्रधानमंत्री के संकल्प को स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के रूप में साकार करने में यह बीएसएल-4 फैसीलिटी माइलस्टोन सिद्ध होगी।

स्वागत भाषण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि जिस तरह भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने में महात्मा गांधी और सरदार पटेल का योगदान रहा है, उसी तरह आधुनिक भारत और गुजरात का भाग्य बदलने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया है।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि गुजरात की यह पहली और देश की अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने में निर्णायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री की परिकल्पना से 'गुजरात स्टेट बायो-टेक्नोलॉजी मिशन' (जीएसबीटीएम) की स्थापना हुई थी। आज उसी विजन के परिणामस्वरूप गुजरात एशिया के प्रथम समर्पित बायो-टेक विश्वविद्यालय वाला राज्य बना है। जिस अनुसंधान सुविधा का आज शिलान्यास हुआ है, वह भारत सरकार द्वारा डेजिग्नेट गुजरात की इस प्रकार की पहली अनुसंधान सुविधा है।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, सांसद सर्वश्री हसमुखभाई पटेल, हरिभाई पटेल, मयंकभाई नायक, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, श्री अल्पेशभाई ठाकोर, भारत सरकार के बायो-टेक्नोलॉजी सचिव श्री राजेश गोखले, राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्री पी. भारती तथा गांधीनगर जिला कलेक्टर श्री मेहुल दवे सहित विभिन्न पदाधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन

(जीएनएस)। ऑल इंडिया एससी/एसटी एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एवं सिग्नल कारखाना शाखा द्वारा आयोजित डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कमर्शियल एवं ट्रैकमैन साबरमती टीमों के बीच खेला गया। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रैकमैन साबरमती टीम विजेता बनी, जबकि कमर्शियल टीम उपविजेता रही। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ श्री अशोक कुमार, Sr. DME वटवा एवं श्री एस.पी. गुप्ता, Sr. DME साबरमती भी उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दिनांक 11.01.2026 को साबरमती इंस्टिट्यूट में आयोजित इस टूर्नामेंट में ट्रैक मेंटेनर एवं कमर्शियल टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में कमर्शियल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 102 रन बनाए। टीम की ओर से श्री शिवकुमार प्रजापत ने शानदार अर्धशतक लगाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रैक मेंटेनर टीम ने मात्र 13.1 ओवर में जीत हासिल कर प्रतियोगिता अपने नाम की। कमर्शियल टीम उपविजेता रही।

कमर्शियल टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए ACM श्री हफीज खान पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के साथ उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यह प्रतियोगिता खेल भावना, टीमवर्क और सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण रही।

आदतन अपराध की जिद: 68 की उम्र, 50 मुकदमे और फिर वही रास्ता, बरकत उर्फ बाबू खान दोबारा गिरफ्तार

(जीएनएस)। बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कानून-व्यवस्था और अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों को हैरान कर दिया है। 68 साल की उम्र, करीब पांच दशक लंबा आपराधिक इतिहास, 50 से ज्यादा मुकदमे और 10 साल से अधिक समय जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बावजूद बरकत उर्फ बाबू खान अपराध की दुनिया से बाहर नहीं आ पाया। एक बार फिर पुलिस ने उसे चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही उसका नाम फिर से लंबे आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।

यह मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सोइनत्रा गांव का है, जहां स्थित आशापुरा माताजी के मंदिर में पिछले एक महीने के भीतर दो बार चोरी की घटनाएं हुईं। पहली चोरी के बाद गांव में चिंता का माहौल था, लेकिन जब दूसरी बार मंदिर को निशाना बनाया गया तो लोगों का गुस्सा और डर दोनों चरम पर पहुंच गए। दूसरी चोरी में चोर मंदिर की तिजोरी से करीब 25 हजार रुपये नकद, एलईडी टीवी, चांदी की छत्र और माइक्रोफोन सेट लेकर फरार हो गए। मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में लगातार चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। लगातार हो रही चोरी के चलते गांव के लोग खुद ही रात में पहरा देने को मजबूर हो गए। दूसरी ओर पुलिस पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। शेरगढ़ थाना पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाकों में रात की गश्त तेज कर दी। इसी दौरान एक रात पुलिस की नजर मंदिर परिसर के आसपास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। पुलिस ने जब उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम बरकत उर्फ बाबू खान बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी से जुड़ा कुछ सामान बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

जांच में सामने आया कि बरकत खान कोई साधारण आरोपी नहीं है। उसके खिलाफ दर्ज यह मुकदमा 50वां है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वह एक आदतन अपराधी है, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा चोरी, नकबजनी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में गुजारा है। जानकारी के अनुसार, उसके खिलाफ पहला मामला साल 1984 में दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक वह लगातार अपराध करता रहा है। उम्र बढ़ने के साथ जहां आमतौर पर लोग जीवन की ढलान पर शांति और सुकून की तलाश करते हैं, वहीं बरकत खान ने अपराध को ही अपनी पहचान बनाए रखा।

पुलिस का कहना है कि आरोपी अब तक 10 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुका है। इसके बावजूद उसमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। हाल ही में वह अजमेर जेल से फरार भी हो गया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। फरारी के दौरान भी उसने चोरी की वारदातों को अंजाम देना बंद नहीं किया। आशापुरा माताजी मंदिर में हुई चोरी की घटनाओं ने आखिरकार उसे फिर से कानून के शिकंजे में ला दिया।

बरकत खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि उससे पूछताछ के जरिए जिले में हुई कई अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इतने लंबे आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति अकेले काम नहीं करता और इसके तार अन्य अपराधियों से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मंदिर चोरी के पीछे कोई और गिरोह सक्रिय था या नहीं।

इस पूरे मामले ने समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कोई व्यक्ति 68 साल की उम्र तक, दर्जनों मुकदमों और लंबी जेल यात्राओं के बाद भी अपराध से क्यों नहीं निकल पाता। क्या यह सुधार की व्यवस्था की असफलता है या फिर अपराध की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि उम्र और सजा भी उसे बदल नहीं पाती। बाड़मेर की यह घटना न सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती है, बल्कि समाज और सिस्टम के लिए भी आत्ममंथन का विषय बन गई है।

शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को भारत ने सिरे से नकारा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होने का दोहराया संकल्प

(जीएनएस)। नई दिल्ली। शक्सगाम घाटी को लेकर चीन द्वारा दोहराए गए दावों पर भारत ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाते हुए उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर चीन का कोई भी दावा न केवल निराधार है बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक तथ्यों के भी खिलाफ है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने चीन को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि बेबुनियाद नक्शों और बयानों के जरिए जमीनी हकीकत नहीं बदली जा सकती और भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। चीन की ओर से यह नया दावा ऐसे समय सामने आया है जब भारत ने हाल ही में शक्सगाम घाटी और आसपास के इलाकों में चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई थी। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में बनाई जा रही हैं और इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो रहा है बल्कि द्विपक्षीय संबंधों में भी तनाव बढ़ रहा है। इसके जवाब में चीन द्वारा अपने नक्शों में शक्सगाम घाटी को शामिल करना और उस पर दावा जताना भारत की नजर में एक उकसावे वाली कार्रवाई है। शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाका है। यह काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर तथा अक्साई चिन जैसे विवादित क्षेत्रों के निकट पड़ता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जम्मू-कश्मीर का हिस्सा रहा है और आज भी भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। हालांकि वर्तमान में यह इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से सटा हुआ है, लेकिन इससे भारत के दावे की वैधता कम नहीं होती। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए तथाकथित सीमा समझौते को भारत ने शुरू से ही अवैध और अमान्य बताया है।

सोना-चांदी के वायदाओं में परस्पर विरुद्ध चाल: सोना वायदा 498 रुपये लुढ़का, चांदी वायदा 1210 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 231176.05 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 45165.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 186003.27 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 37648 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2945.19 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 36563.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 141847 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142206 रुपये और नीचे में 141311 रुपये पर पहुंचकर, 142032 रुपये के पिछले बंद के सामने 498 रुपये या 0.35 फीसदी गिरकर 141534 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 286 रुपये या 0.25 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 115018 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 26 रुपये या 0.18 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14395 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 141877 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142005 रुपये और नीचे में 141004 रुपये पर पहुंचकर, 378 रुपये या 0.27 फीसदी औंधकर 141370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 142399 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142766 रुपये और नीचे में 141600 रुपये पर पहुंचकर, 142440 रुपये के पिछले बंद के सामने 364 रुपये या 0.26 फीसदी औंधकर 142076 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 269701 रुपये के भाव पर खूलकर, 272202 रुपये के दिन के उच्च और 266037 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268970 रुपये के पिछले बंद के सामने 1210 रुपये या 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ 270180 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1308 रुपये या 0.48 फीसदी की तेजी के संग 272043 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1267 रुपये या 0.47 फीसदी बढ़कर 272117 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 5174.97 करोड़ रुपये के ट्रेड

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 45165.21 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 186003.27 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 36563.49 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37648 पॉइंट के स्तर पर

दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 6.2 रुपये या 0.47 फीसदी गिरकर 1309 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 70 पैसे या 0.22 फीसदी चढ़कर 313.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.45 रुपये या 0.46 फीसदी औंधकर 315.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 90 पैसे या 0.47 फीसदी की नरमी के साथ 192.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3422.30 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5359 रुपये के भाव पर खूलकर, 5493 रुपये के दिन के उच्च और 5359 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 133 रुपये या 2.49 फीसदी की तेजी के संग 5468 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 134 रुपये या 2.51 फीसदी की तेजी के संग 5469 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 303.3 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 310.6 रुपये और नीचे में 298.6 रुपये पर पहुंचकर, 304.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.3 रुपये या 1.74 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 309.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 5.3 रुपये या 1.74 फीसदी की तेजी के संग 309.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 995 रुपये पर खूलकर, 2.3 रुपये या 0.23 फीसदी औंधकर 979 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 14839.46 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21724.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4343.29 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 358.80 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 30.63 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 431.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1356.33 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2057.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19980 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 75467 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 24048 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 369370 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 41251 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14425 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 37659 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99116 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24321 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 47931 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 37500 पॉइंट पर खूलकर, 37849 के उच्च और 37300 के नीचले स्तर को छूकर, 36 पॉइंट घटकर 37648 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 58.9 रुपये की बढ़त के साथ 112.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.05 रुपये की बढ़त के साथ 17.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 181.5 रुपये की गिरावट के साथ 1489.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 268000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1120.5 रुपये की बढ़त के साथ 15524 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.07 रुपये की गिरावट के साथ 42 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5 पैसे की नरमी के साथ 3.44 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 69 रुपये की गिरावट के साथ 49.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.8 रुपये की गिरावट के साथ 11.35 रुपये हुआ। सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 66 रुपये की बढ़त के साथ 198 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 67.5 रुपये की गिरावट के साथ 1704.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.94 रुपये की बढ़त के साथ 33.2 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 35 पैसे की नरमी के साथ 1.4 रुपये हुआ।